



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1483]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11, 2015/आषाढ़ 20, 1937

No. 1483]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11, 2015/ASHADHA 20, 1937

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

का.आ.1876(अ).—भारत के राष्ट्रपति और कस्तूरबा सेवा मंदिर न्यास, राजपुरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् केएसएमटी कहा गया है) के बीच निष्पादित पट्टा विलेख द्वारा सरकारी भूमि, उस पर सरकार द्वारा सन्निर्मित भवनों सहित, जिसकी कुल माप 46.93 एकड़ है और जो पंजाब राज्य के राजपुरा-140401 में स्थित है और जो उस करार से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित तथा रेखांक में अंकित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टे पर दी गई भूमि कहा गया है), केएसएमटी द्वारा चलाए जा रहे लोक और पूर्त संबंधी क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए नाममात्र के एक रुपया वार्षिक किराये पर केएसएमटी को, 17 जनवरी, 1959 से तीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी;

और जबकि समय-समय पर उक्त पट्टा बढ़ाया गया था और उसे अंतिम रूप से 16 जुलाई, 2000 से 15 जुलाई, 2004 तक चार वर्ष की और अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए और बढ़ाया गया था कि कस्तूरबा सेवा मंदिर न्यास (केएसएमटी):-

- अपने क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और 16 जुलाई, 2004 से पहले सरकारी भूमि को खाली कर देगा; या
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा यथा नियत प्रचलित बाजार दरों पर पट्टा भूमि खरीदेगा; या
- तत्काल पट्टे पर दी गई भूमि सरकार को सौंप देगा।

और केएसएमटी पूर्वोक्त कथन शर्तों के अनुपालन करने और 16 जुलाई, 2004 को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई भूमि को खाली करने में असफल रहा है;

और संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली दल ने पट्टे पर दी गई भूमि को देखा और यह पाया कि न्यास खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विभिन्न स्कीमों के अधीन लोक तथा पूर्त संबंधी क्रियाकलापों तथा विकासात्मक क्रियाकलापों के स्थान पर बर्फ की कारखाना, किराये पर गोदामों, कृषि उत्पादों और चारे की बिक्री सहित प्राइवेट क्रियाकलाप कार्यान्वित कर रहा है;

और माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के अनुमोदन से तथा विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से पट्टा भूमि को उक्त सूचना की तारीख अर्थात् 11 जून, 2012 से तीन मास की अवधि के भीतर खाली करने के लिए न्यास को एक विधिक सूचना तामील करवाई गई थी;

और न्यास ने विधिक सूचना में यथा उल्लिखित तीन मास की अनुबद्ध अवधि के भीतर भूमि खाली नहीं की थी;

और केंद्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) तारीख 02 जनवरी, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ.14(अ) तारीख 30 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री एल. हौकिप, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को अप्राधिकृत दखलदार अर्थात् केएसएमटी की बेदखली के प्रयोजन के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 की 40) की धारा 3 के अधीन पंजाब राज्य में राजपुरा 140401 की स्थानीय सीमाओं में पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में तीन मास की अवधि के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था;

और तीन मास की उक्त अवधि के भीतर सम्पदा अधिकारी उक्त सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखली प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ नहीं हुए इसलिए केन्द्रीय सरकार ने तारीख 21 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का. आ. 2952 (अ.) द्वारा श्री एल हौकिप निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सम्पदा अधिकारी के रूप में 31 मार्च, 2015 तक की और अवधि के लिए नियुक्त किया;

और सम्पदा अधिकारी ने कस्तूरबा सेवा मंदिर न्यास, राजपुरा और सभी व्यक्ति, जो पट्टे पर दी गई भूमि या उसके किसी भाग के दखल में हो सकते हैं, को निदेश देते हुए उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख के 15 दिन के भीतर उक्त परिसर खाली करने तथा बकाया किराये तथा 10,220.67 लाख रुपये की क्षतियों का भुगतान करने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन तारीख 12 मार्च, 2015 को एक आदेश पारित किया था;

और, कस्तूरबा सेवा मंदिर सेवा न्यास, ने न तो पट्टे पर दी गई भूमि खाली की है या नहीं बकाया किराया और 10,220.67 लाख रुपये की क्षति का संदत्र किया है किंतु सम्पदा अधिकारी के तारीख 12 मार्च, 2015 द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने के लिए जिला और सेशन न्यायालय, पटियाला के समक्ष एक अपील फाइल कर दी है;

और सम्पदा अधिकारी का निबंधन अवसान हो गया है और केएसएमटी द्वारा फाइल अपील को प्रतिवाद अपील करने तथा बेदखली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सम्पदा अधिकारी को समर्थ करने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक है;

अब केन्द्रीय सरकार, तारीख 12 मार्च, 2015 उक्त आदेश के विरुद्ध कस्तूरबा सेवा मंदिर न्यास द्वारा फाइल अपील को प्रतिवाद अपील करने और बेदखली प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयोजन के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पदा अधिकारी के रूप में श्री एल. हौकिप, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को 30 सितम्बर, 2015 तक की और अवधि के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4(33)/86—केवीआई—I]

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

S.O. 1876(E).—Whereas by a lease deed executed between the President of India and the Kasturba Seva Mandir Trust, Rajpura (hereinafter referred to as KSMT), the Government land with buildings constructed thereon by the Government, measuring in all 46.93 acres and situated at Rajpura-140401 in the State of Punjab described in the Schedule to, and delineated on the plan annexed to, the said Agreement (hereinafter referred to as the leased land), was given on lease to KSMT on a nominal yearly rent of rupee one in view of the public and charitable activities carried on by KSMT, with effect from the 17th January, 1959 for a period of thirty years;

And whereas the said lease was extended from time to time and was last extended for a further period of four years with effect from 16th July, 2000 up to 15th July, 2004, subject to the conditions that KSMT shall—

- (i) make alternative arrangements for carrying out its activities and vacate the Government land before 16th July, 2004; or
- (ii) purchase the leased land at the prevailing market rate as fixed by the Central Public Works Department; or
- (iii) handover the leased land to the Government immediately.

And whereas, KSMT failed to comply with the conditions stated above and to vacate the leased land on or before the 16th July, 2004;

And whereas, the team headed by the Joint Secretary visited the leased land and it was observed that the trust is carrying on with private activities including ice factory, renting of godowns, sale of agricultural products and fodder instead of public and charitable activities and developmental activities under various schemes of Khadi and Village Industries Commission;

And whereas, a legal notice was served to KSMT with the approval of Hon'ble Minister of Micro, Small and Medium Enterprises and in consultation with the Ministry of Law and Justice to vacate the leased land within a period to three months from the date of said notice i.e., 11th June, 2012;

And whereas, the trust did not vacate the land within the stipulated period of three months as mentioned in the legal notice;

And whereas, the Central Government had, vide notification number S.O. 14(E), dated 30th December, 2013, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 2nd January, 2014, appointed Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as the Estate Officer for a period of three months in respect of the leased land within the local limits of Rajpura-140401 in the State of Punjab under section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) for the purpose of eviction of unauthorized occupant, namely, KSMT;

And whereas, as the Estate Officer was not able to complete the eviction process under the said Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act within the said period of three months, the Central Government appointed Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as the Estate Officer for a further period up to 31st March, 2015 vide notification number S.O. 2952(E), dated 21st November, 2014;

And whereas, the Estate Officer passed an order dated 12th March, 2015 under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 directing the Kasturba Seva Mandir Trust, Rajpura and all persons in occupation of the leased land or any part thereof, to vacate the premises within 15 days of the date of publication of the said order and to pay or deposit arrears of rent and damages amounting to rupees 10,220.67 lacs within 15 days of the date of publication of the said order;

And whereas, the KSMT has neither vacated the leased land nor paid the arrears of rent and damages of rupees 10,220.67 lacs, but instead has filed an Appeal before the District and Session Court, Patiala to set aside the said order dated 12th March, 2015 passed by the Estate Officer;

And whereas, the term of the Estate Officer has expired and it is necessary to extend the term of office to enable the Estate Officer to contest the appeal filed by the KSMT and to complete the eviction process;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, the Central Government hereby appoints Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as the Estate Officer for a further period upto 30th September, 2015, for the purpose of contesting the appeal filed by the KSMT against the said order dated 12th March, 2015 and to complete the eviction process.

[F. No. 4(33)/86-KVI-I]

B.H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.